दैनिक जागरण

सपने नींद से उठकर ही पूरे किए जा सकते हैं

गंभीर मामला

जितना गंभीर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगना है उतना ही उनका यह कहना भी कि ये आरोप किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं और उनका मकसद है न्यायपालिका को निष्क्रिय करना। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये आरोप ऐसे समय आए जब सुप्रीम कोर्ट कई संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने जा रहा है। यह बेहद गंभीर टिप्पणी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को अस्थिर करने के लिए इस हद तक जाया जा सकता है तो इससे खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती। इस मामले में जो जानकारी सार्वजनिक हुई है उसके आधार पर किसी के लिए भी किसी नतीजे पर पहुंचना कठिन है और पहुंचा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन सच-झूठ की तह तक जाना भी जरूरी है और यह किसी जांच से ही संभव है। यह जांच न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप केवल होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखनी भी चाहिए। यह इसलिए और आवश्यक है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। इन स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये ताकतें न केवल बेनकाब हों, बल्कि कठोर दंड की भागीदार भी बनें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर लगे आरोप सच हैं या झूठ, इसका फैसला चाहे जब और जैसे हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकी कि वह एक तरह से मी-टू की चपेट में आ गए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय अभियान भारत में भी एक अर्से से अपना असर दिखा रहा है।

कार्यस्थलों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक हकीकत है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए किसी सुनिश्चित प्रक्रिया का अभाव ही दिख रहा है। जब कोई नामचीन हस्ती यौन उत्पीड़न के आरोपों से दो-चार होती है तो देश भर में शोर मच जाता है और उसके मामले में अलग व्यवहार होता है, लेकिन जब कोई आम आदमी इस तरह के आरोपों का सामना करता है तो कभी चर्चा नहीं होती और कभी वह आरोप सिद्ध हुए बगैर दंडित हो जाता है। साफ है कि इस तरह के आरोपों की जांच के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की दरकार है जिससे एक ओर जहां यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को न्याय मिले वहीं दूसरी ओर कोई झूठे आरोपों का शिकार न बनने पाए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने के मामले भी पहले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामलों में जब तक सच्चाई सामने आती है, आरोपित की प्रतिष्ठा धूल-धूसरित हो चुकी होती है। ऐसा न हो, इसकी कोई व्यवस्था बननी चाहिए और यह व्यवस्था बने, यह देखना नीति-नियंताओं के साथ न्याय के रखवालों का भी काम है। मुख्य न्यायाधीश पर लगे आरोपों के मामले में यह एक सवाल उठा है कि क्या उन्हें उस बेंच का हिस्सा होना चाहिए जिसने उनके मामले की सुनवाई की? इस सवाल के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत का विवरण मीडिया के एक खास हिस्से में ही आया और उसके पहले यह शिकायत 22 न्यायाधीशों तक पहुंचा दी गई।

छात्र संख्या में गिरावट

उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में दाखिल किए जाने वाले कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या लगातार तेजी से घट रही है। हालत यह है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को दाखिल कराने के लिए शिक्षा महकमे को प्रवेशोत्सव की मुहिम छेड़नी पड़ रही है। इस मुहिम के बावजूद अपेक्षित परिणाम राज्य सरकार और शिक्षा महकमे को नहीं मिल रहे हैं। साल-दर-साल यह समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है, लेकिन इसके समाधान को ठोस रोडमैप अब तक नजर नहीं आया है। राज्य बनने के बाद दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालयों में ही छात्र संख्या 50 फीसद से ज्यादा घट चुकी है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी स्थिति खराब है। अभिभावकों और छात्र-छात्राओं का सरकारी विद्यालयों से मोहभंग बढ़ रहा है। आरटीई के तहत दाखिलों को लेकर सरकार पर पड़ने वाला दबाव भी यही तस्दीक कर रहा है। निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का बोझ 130 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में शिक्षा महकमे के बजट खर्च का आंकड़ा 6200 करोड़ हो गया है। जाहिर है कि सरकार शिक्षा के नाम पर बड़ी धनराशि खर्च कर रही है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में सरकारी शिक्षा की हालत बदतर ही हुई है। सुधार के नाम पर महकमे में विभिन्न स्तरों पर कई प्रयोग चल रहे हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में शिक्षा और विषय ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए कई कदम लगातार उठ रहे हैं, लेकिन ये तमाम कोशिशें अभिभावकों और छात्र-छात्राओं का पर्याप्त भरोसा जीतने में कामयाब होती नहीं दिख रहीं। ऐसा होता तो दूरस्थ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सरकारी विद्यालयों से नजदीकी निजी विद्यालयों में छात्रों का पलायन नहीं होता। छात्र केंद्रित शिक्षा नीति का मूलाधार शिक्षा को मिशन के रूप में ही लिए जाने में ही निहित है। सरकारी तंत्र में इसी का नितांत अभाव है।

फिर सतह पर जाति-मजहब की राजनीति

संजय गुप्त

यदि भारतीय समाज जाति-मजहब के आधार पर मतदान करेगा तो फिर वह मताधिकार का इस्तेमाल करके भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम नहीं कर सकेगा

लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दो दौर समाप्त होने के बाद चुनाव प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ चुनावी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तब भाजपा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल को आगे बढ़ा रही थी और कांग्रेस अपनी न्याय नामक योजना पर जोर दे रही थी, जिसके तहत सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने का वादा किया गया है। इसके अलावा वह राफेल सौदे के बहाने चौकीदार चोर है.. नारे को उछाल कर प्रधानमंत्री मोदी को चोर बता रही थी। ऐसा करके वह प्रधानमंत्री पद का अपमान ही कर रही थी। कांग्रेस के इस आक्षेप का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने चौकीदार शब्द अपने नाम में जोड़ने का फैसला किया। चूंकि पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का देश-दुनिया में खासा असर हुआ इसलिए प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख करना शुरू किया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर हमले भी जारी रखे। इस सबके बीच यह जो उम्मीद की जा रही थी कि आगे आम आदमी के, विकास के और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेंगे वह धूमिल होती जा रही है। राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र के एक-दो बिंदुओं की ही चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं।

विकास के मुद्दों के बजाय चुनाव प्रचार धीरे-धीरे जातीय और मजहबी आधार पर ध्रुवीकरण पर केंद्रित होता जा रहा है। यह शायद इसलिए भी है, क्योंकि औसत मतदाता सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के मुद्दों को उतना महत्व नहीं देते जितना कि देना चाहिए। यदि जाति और मजहब के आधार पर वोट दिए जाएंगे तो फिर विकास के मुद्दे पीछे छूटने तय हैं। राजनीतिक दल इन मुद्दों को छोड़कर भावनात्मक मुद्दों को जिस तरह अहमियत दे रहे हैं वह शुभ संकेत नहीं। विडंबना यह है कि भावनात्मक मसलों को धार देने में कोई भी दल पीछे नहीं दिख रहा है। समझौता एक्सप्रेस कांड के अभियुक्तों के बरी हो जाने के बाद भाजपा की ओर से कांग्रेस पर यह कहकर निशाना साधा गया कि उसने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद का जुमला उछाला। कांग्रेस को इस आरोप का कोई जवाब सूझता, इसके पहले ही भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से अपना उम्मीदवार बना दिया। साध्वी के भाजपा में शामिल होकर भोपाल से प्रत्याशी बनने के पहले ही मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक रैली में बसपा प्रमुख मायावती ने खुले आम अपील की कि मुस्लिम अपना मत बंटने न दें। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अली-बजरंगी बल का सवाल उछाला। चुनाव आयोग ने इन दोनों नेताओं को कुछ दिन के लिए प्रचार करने से रोका, लेकिन दूसरे नेताओं पर इसका असर नहीं पड़ा। बिहार की एक रैली में पंजाब के मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने मुसलमानों से कहा कि वे एकमुश्त वोट देकर मोदी को सबक सिखाएं। मुस्लिम समाज को लुभाने का काम अन्य अनेक नेता भी करने में लगे हुए हैं। वे मुस्लिम समाज को डराने के लिए भाजपा का हौवा खड़ा कर रहे हैं। मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश नई नहीं है। आम धारणा है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उसे वोट देते भी हैं। माना जाता है कि तीन तलाक के मसले पर कुछ मुस्लिम इस चुनाव में भी भाजपा को वोट दे सकते हैं। शायद इससे रोकने के लिए ही उन्हें भाजपा के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश हो रही है।

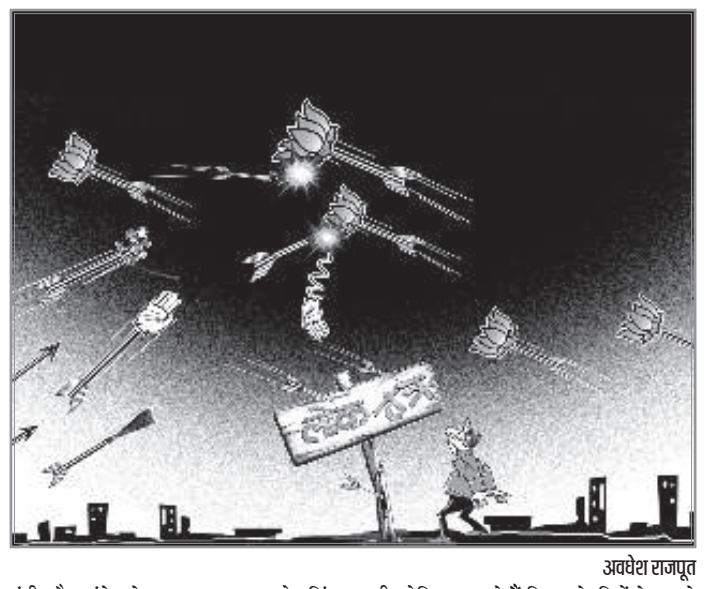

अवधेश राजपूत

समस्या केवल इतनी ही नहीं, मजहबी आधार पर मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश हो रही है। समस्या यह भी है कि जातीय आधार पर भी उन्हें गोलबंद किया जा रहा है। कई राजनीतिक दल विभिन्न जातीय समुदायों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हितों के सच्चे हितैषी वही हैं और इसलिए उनका वोट उन्हें ही मिलना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव पिछड़ी जातियों के ध्रुवीकरण के लिए यहां तक कह रहे हैं कि 85 प्रतिशत आबादी के हक की लड़ाई है, जिस पर 15 प्रतिशत लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनकी मानें तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को मिले आरक्षण के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। बसपा प्रमुख मायावती मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा करके यह कह रही हैं कि वह मोदी की तरह पिछड़ों के नकली नेता नहीं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जाति को चुनावी मुद्दा बनाते हुए यह कह जाते हैं कि उन्हें उनकी जाति के कारण राष्ट्रपति बनाया गया। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक जाति विशेष को निशाना बनाते हुए यह कह जाते हैं कि सारे मोदी चोर होते हैं।

अपने देश में जातीय आधार पर राजनीति भी कोई नई बात नहीं, लेकिन मंडल आयोग की रपट लागू होने के बाद इस तरह की राजनीति ने कहीं तेजी पकड़ी है। इसके तहत आरक्षण संबंधी मांगों को हवा दी जाती है। दलित-पिछड़ी जातियां इसलिए जातिवादी राजनीति करने वालों की ओर आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि वे विकास की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन सकी हैं। दलित-पिछड़ी जातियों को यह आभास कराया जाता है कि शासन-प्रशासन में उनकी अपेक्षित भागीदारी नहीं। निःसंदेह यह एक सच्चाई है, लेकिन यह कहना कठिन है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था दलित-पिछड़ी जातियों की समुचित भागीदारी के सवाल को सही तरह से हल करने में सक्षम है। संकट यह है कि कोई भी दल इसके लिए तैयार नहीं कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करके ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे पीछे छूट गए लोग सही तरह से लाभान्वित हो सकें। राजनीतिक दल और खास तौर पर क्षेत्रीय दल पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन का सवाल उठाकर उनकी भावनाओं को भुनाने का काम ही अधिक कर रहे हैं। यही काम गरीबी दूर करने के नाम पर भी हो रहा है। मुश्किल यह है कि गरीब तबका और पिछड़ी जातियां यह नहीं देख पा रही हैं कि उनके पिछड़ेपन को चुनावों में भुनाने का काम किस तरह वे लोग कर रहे हैं जो आरक्षण का पात्र न होते हुए भी उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर आरक्षण संबंधी क्रीमी लेयर इसी तरह कायम रही तो शायद ही पिछड़ों में जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का सही लाभ मिल पाए।

चुनाव के मौके पर अगड़े-पिछड़े का सवाल जिस तरह सतह पर आता है उससे भारतीय समाज विभाजित ही होता है। निःसंदेह यही काम मजहबी आधार पर लोगों को गोलबंद करने की कोशिश के कारण भी होता है। यदि भारतीय समाज जाति-मजहब के आधार पर विभाजित होकर मतदान करेगा तो फिर वह मताधिकार का इस्तेमाल करके भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम नहीं कर सकेगा।

response@jagran.com

बड़े काम का छोटा नाम

सूर्यकुमार पांडेय

अब विश्वमोहन जी सिर्फ वीएम रह गए हैं। ऐसे में अगर ईवीएम की कृपा हो गई तो वह फिर से एमपी बनेंगे

यह विशुद्ध शॉर्टकट का दौर है। संक्षिप्तता ही सामान्य दस्तूर बन गई है। वही चलन में है। मसलन सीएफएल, एटीएम, सिम, जीएसएम, सीडीएमए आदि-इत्यादि। जो लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं वे तक नहीं जानते हैं कि इन शब्दों की फुलफॉर्म क्या हैं? यदि छोटे रास्ते से काम बन रहा है तो लंबी राह कोई भी नहीं चुनना चाहता है। अब तो लोगों के नामों तक का संक्षिप्तीकरण होने लग गया है। हमारे क्षेत्र के एक निवर्तमान सांसद बाबू विश्वमोहन प्रताप नारायण सिंह को ही देख लीजिए। एक जमाने में क्या ही लंबा-चौड़ा नाम हुआ करता था। भारी-भरकम रुतबा भी था, इसीलिए सांसद भी बने थे, लेकिन बनने के तत्काल बाद ही किसी समर्थक ने सुझाव दिया था-भैया जी, अब आप माननीय हो गए हैं। कल को आप मंत्री भी हो सकते हैं। तब आपके नाम के आगे बाबू लगा होने से लोगों को भ्रम हो सकता है कि आप पहले किसी सरकारी कार्यालय में लगे रहे होंगे, तो इसको हटाइए। बाबू विश्वमोहन प्रताप नारायण सिंह बोले- वाकई तुमने उचित परामर्श दिया है। अब तो बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी भी मेरे सामने कुर्सी छोड़कर खड़े होते हैं। इसलिए मैं आज से ही अपने नाम के आगे न बाबू लगाऊंगा और न ही किसी को लगाने दूंगा। इस तरह वह बाबू का परित्याग कर अब मात्र विश्वमोहन प्रताप नारायण सिंह ही रह गए।

विश्वमोहन प्रताप नारायण सिंह के सांसद बनने के लगभग दो महीने बाद एक और वाकया हुआ। किसी नवोदित सजातीय चमचे ने फरमाया, 'सर, चुनाव में धनबल, गनबल और जनबल के चलते ही आपकी विजय हुई थी। अब आप जीतकर निश्चिंत हो लिए हैं। दिन-रात अपने लोगों के ही विकास की बातें सोचते रहते हैं। उधर आपके विपक्षी दल आप पर आरोप लगाने लगे हैं। वे सब कहने लग गए हैं कि आप जन-जन के नेता नहीं हैं। आप तो बस अपनी जाति के लोगों की तरक्की की ही बातें सोचते हैं। इसलिए मेरा सुझाव मानिए और अपने जातिनाम का परित्याग कर दीजिए। विश्वमोहन प्रताप नारायण सिंह को यह सुझाव भी सार्थक और सामयिक लगा था। हालांकि चुनाव जातीय समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण और अपने लोगों की मेहनत के बल पर ही जीते जाते हैं तथापि अन्य जाति-धर्म के मतदाताओं में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। आगे भी तो जनता के बीच वोट मांगने जाना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद से विश्वमोहन प्रताप नारायण सिंह घट-घटाकर विश्वमोहन प्रताप नारायण ही तक सिमटकर रह गए।

एक बार विश्वमोहन प्रताप नारायण अपनी पार्टी के आलाकमान से मिलने पहुंचे। आलाकमान ने कहा- विश्वमोहन प्रताप नारायण जी, आपका यह नाम जरूरत से कुछ अधिक लंबा है। आज के समय में यह नहीं चलेगा। आज की राजनीति को समझिए। अब पार्टियां तक भाजपा, सपा, बसपा, रालोद, सीपीआइ, सीपीएम, जदयू, आप और हम तक बोली जाती हैं। लंबे नाम पहले भी हुआ करते थे। मसलन जयप्रकाश नारायण और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता भी जेपी और वीपी नामों से ही पहचाने गए। अब आप भी अपने नाम को तनिक छोटा कर लें तो उचित रहेगा। अब विश्वमोहन प्रताप नारायण किस मुंह से कहते कि पहले ही अपने मूल नाम का आगा-पीछा कटवा चुके हैं। आलाकमान के सामने न किसी का कोई तर्क चलता है और न मुंह खोलने की जुर्रत होती है। वे बाहर निकले और तुरंत घोषणा कर दी कि आज से अब मेरा नाम विश्वमोहन हो गया है। मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना जाए।

कहते हैं, वोटर की स्मरणशक्ति कमजोर होती है। वह अपने नेताओं के पिछले कृत्य भुला देती है तो भला बाबू विश्वमोहन प्रताप नारायण सिंह के नाम की क्या ही औकात थी? सो वे भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में विश्वमोहन जी के नाम से लोकप्रिय हो गए। बहुतों को तो यह तक याद नहीं रहा कि ये वाले वो ही हैं! इस बीच बाबू विश्वमोहन प्रताप नारायण सिंह ने नाम के बाद अपना दल-बदल भी कर लिया था। चेहरा-मोहरा, स्वास्थ्य, पहनावा, रहन-सहन सब बदल चुके थे। लोग तो यहां तक कहने लग गए थे कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। इस बार भी विश्वमोहन जी चुनाव में खड़े हैं। अब विश्वमोहन का नाम और भी संक्षिप्त होकर वीएम रह गया है। इस छोटे से नाम के साथ वह चुनावी तकदीर का फैसला करने वाली ईवीएम के दूर के रिश्तेदार भी लगने लगते हैं। ऐसे में अगर ईवीएम की कृपा हो गई तो वह फिर से एमपी बनेंगे। यदि पीएम की कृपा हो गई तो वीएम जी मंत्रिपद की शपथ भी खा लेंगे। तब डीएम, एडीएम, एसडीएम, सीजीएम, जीएम, डीजीएम, एजीएम एएम से पीएम तक चौबीसों घंटे उनकी सेवा में तत्पर पाए जाएंगे।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | कहां कितना डाउनलोड हुआ टिक टॉक एप

2019 की पहली तिमाही तक (संख्या लाख में)

स्रोत: प्रिओरी डाटा

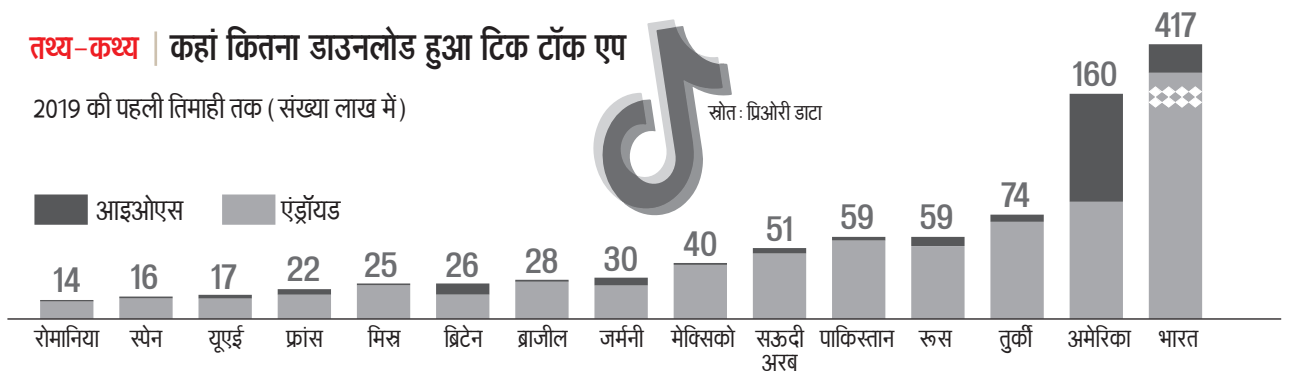

ऊर्जा

दृष्टिकोण

भावना के अनुरूप ही दृष्टिकोण उपजता है और जैसा दृष्टिकोण बन जाता है, कालांतर में वैसी ही भावनाएं जन्मने लगती हैं। भावनाएं और दृष्टिकोण एक दूसरे के कारक भी हैं और परिणाम भी। दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं। भिन्न भाव-भूमि पर अवस्थित किसी एक ही वस्तु के प्रति लोगों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। पानी से आधे भरे गिलास के प्रति भी लोगों का प्रायः दो तरह का दृष्टिकोण देखने को मिलता है। कुछ लोग उसे आधा भरा देखते हैं तो कुछ लोग उसे आधा खाली। जो जिस भाव से देख रहा होता है, उसे गिलास वैसा ही दिखता है। यह दृष्टिकोण भिन्नता है। व्यक्तित्व की भिन्नता ही किसी व्यक्ति के उत्थान-पतन का कारण बनती है।

उचित दृष्टिकोण व्यक्तित्व के गुणों का विकास करता है। वहीं कुदृष्टिकोण व्यक्तित्व के दोषों और विनाश का कारण बनता है। सुदृष्टिकोण अपनी आशामयी प्रवृत्ति के कारण जीवन शक्ति का संचारक और संवाहक बनकर उसे सफल, सुखद, सरस और समृद्ध बनाता है, जबकि कुदृष्टिकोण अपनी निराशावादी प्रकृति के कारण जीवन को निगल लेने वाले अंधकार को नित गहनतर करता जाता है। वह अपने चारों ओर उदासी, भय और कुंठा का वातावरण निर्मित करता रहता है। अवसादों और तनावों के कुहासे में अपने को घेरे रहता है।

सुदृष्टिकोण सक्रिय ऊर्जा देता है, जिससे कोई भी व्यक्ति न तो अपने को ठगा अनुभव करता है और न ही हताश और न ही अशक्त। प्राणी अपनी इस चिरस्फूर्तिता को सुकृत्यों में परिवर्तित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव क्रियाशील रहता है। ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्ति नया संसार रचते हैं। उनके ही प्रयास का प्रतिफल नए-नए आविष्कारों, अनुसंधानों और अन्वेषणों के रूप में सामने आता है। ऐसे लोग ही सुरक्षा के कवच गढ़ते हुए सृजन के बीज बोते हैं। उनके ही ही मार्गदर्शन में उन्नत शिक्षा के फूल खिलते हैं और रचनात्मक शांति की शीतल वायु प्रवाहमान होती है। उनकी ही छांव में श्रेष्ठ विचारों का उत्सर्जन होता है और हितकारी साहित्य और ललित कलाओं का विकास होता है। नैतिकता, निष्ठा और निर्मलता की परिभाषाएं उन्हीं के द्वारा गढ़ी जाती है। ऐसे सुदृष्टिकोण सम्पन्न व्यक्ति ही समाज के आदर्श होते हैं।

वेद प्रकाश मिश्र

ब्रह्मांड उत्पत्ति के खुलते भेद

मुकुल व्यास

खगोल वैज्ञानिक अब अधिक भरोसे के साथ अपने दूसरे अनुमानों के साक्ष्य जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं

ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मांडीय महाविस्फोट के बाद लाखों वर्ष तक कोई आकाशगंगा नहीं थी। तारे नहीं थे और मॉलिक्यूल्स (अणु-समूह) भी नहीं थे। समूचा ब्रह्मांड आण्विक रूप में ही मौजूद था। अणुओं से अणु समूह या मॉलिक्यूल्स के निर्माण में बहुत समय लगा। वैज्ञानिक काफी समय से यह अनुमान लगा रहे थे कि ब्रह्मांड में निर्मित होने वाला सबसे पहला मॉलिक्यूल हीलियम हाइड्राइड था, लेकिन अभी तक किसी ने भी अंतरिक्ष में इसकी मौजूदगी का पता नहीं लगाया था। लेकिन अब नासा के वैज्ञानिकों ने एनजीसी 7027 नामक प्लेनेटरी नेब्यूला में हीलियम हाइड्राइड की मौजूदगी की पुष्टि की है।

यह गैस और धूल का बादल 3,000 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस नक्षत्रमंडल में स्थित है। यह सूरज जैसे किसी तारे का अवशेष है जो अनेकों वर्ष पहले नष्ट हो गया था। आरंभिक ब्रह्मांड बहुत गर्म था और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन के अणुओं के अलावा किसी और चीज की मौजूदगी संभव नहीं थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड को ठंडा होने में करीब एक लाख वर्ष लगे। तभी पहले मॉलिक्यूल्स के निर्माण के लायक परिस्थितियां बनीं। हाइड्रोजन और हीलियम के अणुओं से हीलियम हाइड्राइड बनी, जैसे-जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, हाइड्रोजन के अणुओं ने हीलियम हाइड्राइड के साथ क्रिया की। इस प्रक्रिया में मॉलिक्युलर हाइड्रोजन उत्पन्न हुई जिसने पहले तारों को जन्म दिया।

तारों के अंदर हाइड्रोजन सभी भारी धातुओं में जुड़ी, जिन्हें हम आधुनिक ब्रह्मांड में देखते हैं। नासा ने हीलियम हाइड्राइड को कुछ 'अटपटा' मॉलिक्यूल बताया है। हीलियम एक नोबल गैस है जो मुश्किल से किसी और तत्व के साथ जुड़ती है, लेकिन दशकों पहले किए गए प्रयोगों के दौरान पता चला था कि हीलियम हाइड्राइड निर्मित करना संभव है, लेकिन मॉलिक्यूल को कुदरती तौर पर निर्मित करने वाली परिस्थितियां बहुत ही दुर्लभ होती हैं। खगोल वैज्ञानिक अब यह साबित करने में सफल रहे हैं कि हीलियम हाइड्राइड का निर्माण उन परिस्थितियों में कुदरती तौर पर हो सकता है जो प्रारंभिक ब्रह्मांड की परिस्थितियों से मेल खाती हैं। वैज्ञानिक काफी समय से यह कयास लगा रहे थे कि एनजीसी 7027 में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ऊष्मा का मेल बहुत उपयुक्त है।

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के वायुमंडल में हस्तक्षेप को कम करने के लिए सोफिया के उपकरणों को एक बोइंग 747 एसपी विमान के साथ एकीकृत किया। यह विमान करीब 14 किलोमीटर ऊंचा उड़ सकता है। सोफिया के 270 सेंटीमीटर के टेलीस्कोप में हाल ही में एक नया उपकरण जोड़ा गया था जिससे हीलियम हाइड्राइड को स्कैन करना आसान हो गया था। खगोल वैज्ञानिकों ने जब इस उपकरण को एनजीसी 7027 की तरफ लक्षित किया, उन्हें हीलियम हाइड्राइड का संकेत मिल गया। अनुमानित स्थान पर हीलियम हाइड्राइड की उपस्थिति की पुष्टि प्रारंभिक ब्रह्मांड को समझने की दिशा में अहम कदम है। पृथ्वी पर हीलियम हाइड्राइड का बहुत सीमित महत्व है, लेकिन ब्रह्मांड में केमिस्ट्री की शुरुआत इसी से हुई। इस खोज के बाद खगोल वैज्ञानिक अब अधिक विश्वास के साथ अपने दूसरे अनुमानों के साक्ष्य जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

राजा की चुप्पी

चुनावी दंगल में फिलहाल जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है, वह मध्य भारत की भोपाल सीट है। जहां राजा के सामने साध्वी मैदान में है। मुकाबला काफी रोचक है। इस बीच साध्वी की ओर से राजा पर तीखे हमले किए जा रहे है, पर राजा लंबी चुप्पी साधे हुए है। यह बात अलग है कि उनकी ओर से दूसरे लोग मोर्चा संभाले हुए हैं, पर राजा की इस चुप्पी की भारी चर्चा है। दरअसल, उनका पहले भी एक साध्वी से मुकाबला हो चुका है, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश में वापसी को लेकर एक लंबा वनवास झेलना पड़ा। ऐसे में अब जब फिर से एक साध्वी से उनका आमना-सामना हो रहा है तो वह संभल कर और चुप रहने में भी ही अपनी भलाई समझ रहे हैं।

गलत वकील का खामियाजा

आखिरकार चुनाव आयोग बिगड़े बोल बोलने वाले नेताओं के खिलाफ कारवाई करने पर मजबूर हुआ, लेकिन आयोग को मलाल इस बात का रहा कि उसका किया हुआ कड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आया। वैसे तो आयोग ने बिगड़ते हालातों को ध्यान में रखते हुए बीते रविवार को ही इन नेताओं पर फैसले लेने का विचार कर लिया था, पर कोर्ट में आयोग का पक्ष रखने पहुंचे वकील साहब इससे अवगत नहीं थे। जिसके चलते मजबूरन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी। कोर्ट में आयोग का सख्त फैसला सामने रखने के बजाय वकील साहब उलटा अपने अधिकार क्षेत्र व शक्तियों का हवाला दे आए, जिससे आयोग और पानी-पानी हो गया। बाद में डैमेज कंट्रोल में लगे अधिकारी सबको समझाते फिरते रहे कि कोर्ट की डांट और आयोग के फैसले दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं।

किस्सा मेहनत का

चुनाव में एक चर्चा बहुत तेज हो रही है कि आखिर राजनीति में मेहनती कौन है। इसकी अलग-अलग तरह से समीक्षा हो सकती है, लेकिन नेताओं को रैलीस्थल तक पहुंचाने वाले फ्लाइट कैप्टन का अपना नजरिया है। वह यह देखते हैं कि अलग-अलग दलों के कौन-कौन से नेता समय से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और कौन बस रैलीस्थल को छूकर भागने की फिराक में रहते हैं। उनकी जुबानी एक नेता पूर्वोत्तर में दो रैलियों के लिए गए थे। शाम छह बजे सूर्यास्त होना था और इसलिए जरूरी था कि रैली से वापस आकर उससे पहले दिल्ली के लिए उड़ान भर लें। वक्त सिर्फ डेढ़ घंटे का था। बहुत मुश्किल था दो रैली करना। पार्टी के लिए दोनों रैली जरूरी थीं। नेता जी ने कुछ इतनी जल्दबाजी दिखाई कि एक ही घंटे में दोनों रैली निपटाकर चले आए। सभी अचरज में थे और नेता जी के साथ चल रहे कार्यकर्ता असहज। आखिर इतनी जल्दी तो केवल सभास्थल को छूकर ही आया जा सकता था।

उड़ान का इंतजार

मौसम चुनाव का हो तो ऐसे नेताओं की पूछ बढ़ ही जाती है जो बढ़िया भाषण दे सकें या फिर भीड़ जुटा सकें। ऐसे में पार्टियां खास स्टार प्रचारकों को विमान या हेलीकॉप्टर मुहैया कराती हैं। कांग्रेस में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा कुछ चुनिंदा लोगों को ही विमान या हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया है। इनमें पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं जिनकी चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों में जबरदस्त मांग है। जबकि संसाधनों की चुनौती की वजह से स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कई वरिष्ठ नेताओं को विशेष विमान तो दूर हेलीकॉप्टर भी पार्टी मुहैया नहीं करा पा रही। ऐसे में नियमित उड़ान या सड़क मार्ग से प्रचार के लिए जाने से कई नेता हिचक रहे हैं। जो प्रचार के लिए जा भी रहे उनकी गति धीमी है। कुछ दिग्गज तो हर दूसरे-तीसरे दिन चुनाव प्रबंधकों से खाली विमान या हेलीकॉप्टर की जानकारी ले रहे। जवाब हां में मिला तो वे प्रचार के लिए उड़ान भर लेते हैं और न हुआ तो अगली खाली तारीख तक इंतजार। देखते हैं कि उनका यह इंतजार आखिर कब तक पूरा हो पाता है?

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस